

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 केजरीवाल 20 सितंबर से हरियाणा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे 06 सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव 08 भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं खिलाफ मामला दर्ज किए

दिल्ली में ई-ग्रामीण सेवा चलने का हो गया रास्ता साफ, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक में बदलने को दी मंजूरी, अब रोड पर दौड़ेंगे दुकुराल इलेक्ट्रिक, सारथी, मर्करी व अन्य कंपनियों के ई-ऑटो

संजय बाटला

नई दिल्ली। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की मंशा से दिल्ली सरकार ने मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दे दी है। ग्रामीण सेवा वाहनों के 15 साल पूरे होने को है और इनमें ज्यादातर वाहनों की हालत जर्जर हो चुकी है। यह निर्णय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिल्ली सरकार की नीति के अनुरूप है और इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण सेवा 2011 में शुरू की गई थी। इनमें ड्राइवर को छोड़कर छह यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। ये वाहन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, अनधिकृत और पुनर्वास कॉलोनियों और जेजे समूहों में चलते हैं। पूरी दिल्ली में 2,000 से अधिक ग्रामीण सेवा चल रहे हैं।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, 'रपुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्लीवासियों के लिए यात्रा अनुभव बेहतर और सुगम होगा।'

ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

01. मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहन के बदले में नया इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन खरीदने का इरादा रखने वाले वाहन के पंजीकृत मालिक को मौजूदा ग्रामीण सेवा के प्रतिस्थापन के लिए केवल ऑनलाइन फेसलेस, आधार आधारित पुष्टि या आधार की अनुपलब्धता के मामले में नामांकन आईडी (ईआईडी) के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकारी (डीटीओ/एआरयू) को आवश्यक आवेदन करना होगा।



02. पंजीकरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के बाद 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन फेसलेस प्रक्रिया के माध्यम से कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र (एनडीसी) जारी करेगा कि मौजूदा वाहन के खिलाफ रोड टैक्स/बकाया चालान आदि के रूप में कोई सरकारी बकाया नहीं है, वाहन एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) पोर्टल पर स्पष्ट है और यदि कोई हो, तो दृष्टिबंधक समाप्त हो गया है। यदि ऐसी कोई विसंगति पाई जाती है, तो पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा वाहन के पंजीकृत मालिक को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा और पंजीकृत मालिक को सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर विसंगति को दूर करना होगा। यदि मौजूदा वाहन के मालिक के खिलाफ कोर्ट केस/एफआईआर दर्ज है और यह एक गैर-जमानती अपराध है, तो नए वाहन पंजीकरण अनुरोध के साथ संबंधित अदालत द्वारा मामले को सुलझाए जाने के दस्तावेजी साक्ष्य का ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

03. पुराने वाहन को स्कैप को एनडीसी प्राप्त करने के बाद वाहन को 15 दिनों के भीतर

अधिकृत स्कैपिंग सुविधा में ले जाना होगा। वाहन स्कैप होने पर मालिक को जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) मिलेगा।

04. पंजीकृत मालिक आरवीएसएफ से जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) और ऑटो रिकशा इकाई से एनडीसी प्राप्त करने के बाद किसी भी अधिकृत डीलर से चालक को छोड़कर 6 यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदेगा। वाहन खरीदने के बाद पंजीकृत मालिक को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। वाहन को आवश्यक दस्तावेजों जैसे एनडीसी के साथ पंजीकरण प्राधिकारी के पास जमा करना होगा। यह प्रक्रिया भी फेसलेस है और इसमें वाहन निर्माता से एनडीसी, सीओडी, आधार, टैक्स चालान और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

05. परमिट नवीनीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी सभी विवरणों को सत्यापित करेंगे और ग्रामीण सेवा योजना के तहत वाहन के पंजीकरण को अपडेट करेंगे। नए वाहन को पुराने वाहन के समान मार्ग का ही परमिट मिलेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार परिवहन विभाग (ऑटो रिक्शा और टैक्सी इकाई) 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054
एफ. सं. डीटीओ (एआरयू/टीयू)/टीपीटी/2015/102/सीडीएनओ.075341935/7423/51708 दिनांक:- 18/09/24

आदेश

परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी ने वर्ष 2010-11 में ग्रामीण सेवा योजना के तहत पंजीकृत वाहनों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता की जांच की और यह आदेश दिया गया कि मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 6 यात्रियों और एक चालक की बैठने की क्षमता होगी, जो सीएमवीआर 1989 के नियम 126 के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिकृत परीक्षण एजेंसी द्वारा विधिवत अनुमोदित होगा, जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा:-

(1) मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहन के बदले में नया इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन खरीदने का इरादा रखने वाले वाहन के पंजीकृत मालिक को मौजूदा ग्रामीण सेवा के प्रतिस्थापन के लिए केवल ऑनलाइन फेसलेस, आधार आधारित पुष्टि या आधार की अनुपलब्धता के मामले में नामांकन आईडी (ईआईडी) के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकारी (डीटीओ/एआरयू) को आवश्यक आवेदन करना होगा।

(2) पंजीकरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के बाद 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन फेसलेस प्रक्रिया के माध्यम से कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र (एनडीसी) जारी करेगा कि मौजूदा वाहन के खिलाफ रोड टैक्स/बकाया चालान आदि के रूप में कोई सरकारी बकाया नहीं है, वाहन एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) पोर्टल पर स्पष्ट है और यदि कोई हो, तो दृष्टिबंधक समाप्त हो गया है। यदि ऐसी कोई विसंगति पाई जाती है, तो

पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा वाहन के पंजीकृत मालिक को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा और पंजीकृत मालिक को सूचना प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर विसंगति को दूर करना होगा। यदि मौजूदा वाहन के मालिक के खिलाफ कोर्ट केस/एफआईआर दर्ज है, और यह एक गैर-जमानती अपराध है, तो नए वाहन पंजीकरण अनुरोध के साथ संबंधित अदालत द्वारा मामले को सुलझाए जाने के दस्तावेजी साक्ष्य का ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

(iii) वाहन का पंजीकृत स्वामी उपरोक्त (ii) के अनुसार एनडीसी प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, तथा वाहन को 15 दिनों के भीतर किसी भी अधिकृत पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्कैपिंग के लिए प्रस्तुत करेगा।

(iv) पंजीकृत मालिक आरवीएसएफ से जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) और ऑटो-रिकशा इकाई से एनडीसी प्राप्त करने के बाद, किसी भी अधिकृत डीलर से चालक को छोड़कर 6 यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले अनुमत इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदेगा।

वाहन खरीदने के बाद पंजीकृत मालिक को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। वाहन को आवश्यक दस्तावेजों जैसे एनडीसी के साथ पंजीकरण प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।

सीओडी, आधार (या आधार उपलब्ध न होने की स्थिति में ईआईडी), टैक्स चालान आदि, फॉर्म 20, -1

18 सितंबर 24 फॉर्म 21, वैध बीमा और वाहन निर्माता द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज जैसे कि निर्माता चालान आदि, प्रारंभिक जांच के समय पुराने रूट परमिट के साथ ग्रामीण सेवा योजना के तहत वाहन का पंजीकरण। आवेदन प्रक्रिया चेहराबिहीन हो जाएगी।

(vi) पंजीकरण प्राधिकारी वाहन पर सीओडी विवरण का सत्यापन करने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण की अनुमति देगा।

(vii) ग्रामीण सेवा को जारी किया गया परमिट उसी मार्ग तथा अन्य सभी संबंधित विवरणों के लिए होगा, जिसमें नए वाहन का पंजीकरण नवीनीकृत परमिट पर अद्यतन किया जाएगा।

उप आयुक्त (परिवहन) एफ. सं. डीटीओ (एआरयू/टीयू)/टीपीटी/2015/102/सीडीएनओ.075341935/7423/51708 दिनांक:- 18/09/24 प्रति लिपि प्रेषित:-

1. ओएसडी, माननीय परिवहन मंत्री, जीएनसीटीडी।
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त परिवहन विभाग जीएनसीटीडी के निजी सहायक।
3. विशेष आयुक्त (एआरयू और टीयू), परिवहन विभाग जीएनसीटीडी के पीए।
4. सचिव (एसटीए) परिवहन विभाग जीएनसीटीडी के पीए।
5. उप सचिव (एसटीए) परिवहन विभाग जीएनसीटीडी।
6. विभिन्न यूनिट प्रतिनिधि।

लेह-दिल्ली रूट पर निगम की बस सेवा बंद, अब अगले साल मई-जून में चलेगी

परिवहन विशेष न्यूज

एचआरटीसी के केलोंग डिपो ने लेह-दिल्ली बस सेवा को बंद कर दिया है। निगम ने इस बार 10 जून को लेह-दिल्ली के बीच बस सेवा शुरू की थी और करीब तीन माह तक यह बस लेह से दिल्ली के बीच चली।

हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलोंग डिपो ने लेह-दिल्ली बस सेवा को बंद कर दिया है। अब इस मार्ग से यात्री अगले सीजन मई-जून में सफर कर सकेंगे। हालांकि, अभी मनाली-लेह मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन एचआरटीसी के केलोंग डिपो ने अधिकारिक रूप से लेह-दिल्ली बस सेवा को बंद करने का फैसला लिया है।

निगम ने इस बार 10 जून को लेह-दिल्ली के बीच बस सेवा शुरू की थी और करीब तीन माह तक यह बस लेह से दिल्ली के बीच चली। अब यात्रियों को मनाली-केलांग-लेह के बीच टैक्सियों में मंहगा सफर करना पड़ेगा। निगम की बस में लेह से दिल्ली प्रति सीट का किराया 1,657 रुपये है। यह सफर करीब 30 घंटे का है। एचआरटीसी केलांग डिपो के कार्यकारी क्षेत्रीय प्रबंधक आयुष उपाध्याय ने बताया



कि अधिकारिक निर्देशों का पालन करते हुए लेह-दिल्ली के बीच बस सेवा को बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब लेह की तरफ बारालाखा में मौसम खराब होते ही बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। जेएंडके ने केलांग तक शुरू की बस

एचआरटीसी केलांग डिपो का लेह-दिल्ली रूट पर बस सेवा बंद होने पर जेएंडके ने लेह-केलांग के बीच बस सेवा शुरू की है। दो दिन से यह बस सेवा चल रही है। अड्डा प्रभारी केलांग रतन ने कहा कि दो दिन से यह बस आ रही है।

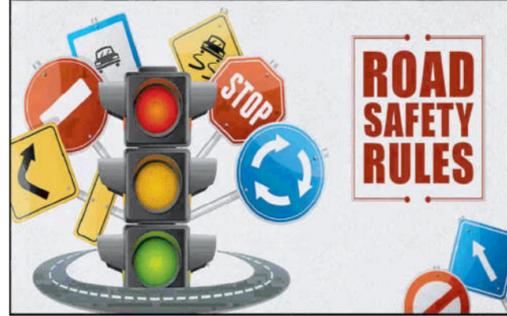
स्थानीय सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता: रोड सेफ्टी स्क्वाड का सराहनीय प्रयास

डॉ. अंकुर शरण

सड़क पर लगने वाले जैम, ट्रैफिक की समस्याओं और रोड रेज जैसी घटनाओं के कारण न केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है, बल्कि समाज की मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, #VocalForLocalRoadSafety अभियान के तहत रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) फरीदाबाद, स्वयंसेवकों की टीम सक्रिय हो गई है। यह टीम सड़क पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एक नई पहल की शुरुआत कर रही है, जिसमें स्थानीय ट्रैफिक अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त है।

इस अभियान का उद्देश्य सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करना है, जिसके लिए नागरिक समाज और अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से समाधान खोजा गया है। यह पहल न केवल सड़क पर अनुशासन और यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने का प्रयास है, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रख रही है।

प्रमुख स्थल और निगरानी रोड सेफ्टी स्क्वाड द्वारा शेर शाह



सूरी रोड, बंगाल शूटिंग चौक, और पुलिस लाइन चौक जैसे व्यस्त स्थानों पर ट्रैफिक प्रबंधन और जाम को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन क्षेत्रों को अब निगरानी में रखा गया है ताकि यातायात में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचा जा सके। टीम सुनिश्चित कर रही है कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।

“ब्लेम गेम” खत्म, समय है जमीन पर उतरने का

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब “दोषारोपण” के बजाय सभी लोग सक्रिय रूप से सड़क सुरक्षा पर काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। यह समय है जब हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सड़क सुरक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। यह सिर्फ अधिकारियों का काम नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वे सड़क पर अनुशासन का पालन करें और जाम से मुक्त सड़कों का निर्माण करें।

अनुशासन और सख्त नियमों की

आवश्यकता यातायात को सुचारू बनाने और सड़क को जाम मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना न केवल सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि खुद की भी। इसलिए यह अनिवार्य है कि हर नागरिक इन नियमों का पालन करे और यातायात को सुगम बनाए।

#VocalForLocalRoadSafety अभियान के माध्यम से रोड सेफ्टी स्क्वाड ने एक सराहनीय शुरुआत की है। सड़क पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह प्रयास निश्चित रूप से एक प्रेरणादायक कदम है और इससे अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की पहल शुरू होने की उम्मीद है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का समय आ गया है, और यह अभियान एक नई दिशा में पहला कदम है।

roadsafetysquad@gmail.com X@RoadSafetySquad

टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website: www.tolwa.in
Email: tolwadelhi@gmail.com
bathasanjaybathia@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बगाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ोदा दिल्ली 110042

फरीदाबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या: नगर निगम की लापरवाही से बढ़ा खतरा



परिवहन विशेष न्यूज फरीदाबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या शहर के यातायात और सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। विडंबना यह है कि जहां नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वह इन आवारा पशुओं को सड़कों से हटाए, वहीं उनके खुद के कार्यालयों के आसपास भी इन पशुओं की भरमार देखी जा सकती है। फरीदाबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को लेकर केतन सूरी द्वारा साझा की



गई जमीनी रिपोर्ट ने एक बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति का खुलासा किया है। यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि शहर की सड़कों आवारा पशुओं से पूरी तरह भर चुकी हैं, जिससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। फरीदाबाद की प्रमुख सड़कों पर आवारा गायों, कुत्तों और अन्य जानवरों की मौजूदगी से न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि रोजाना दुर्घटनाओं की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।



स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए कोई सख्त कदम न उठाए जाने से यह संकट और भी विकराल हो गया है। आवारा पशुओं से यातायात प्रभावित आवारा पशु सड़क पर अचानक आकर ट्रैफिक के बहाव को रोक देते हैं, जिससे वाहन चालकों को न केवल परेशानी होती है बल्कि दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। यह स्थिति न सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यातायात को सुचारू रखने में भी बड़ी चुनौती बन रही है। लापरवाही और कमजोर प्रवर्तन फरीदाबाद नगर निगम की ओर से आवारा पशुओं को हटाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण यह समस्या लगातार बढ़ रही है। प्रवर्तन की कमी और प्रशासनिक उदासीनता ने सड़कों पर आवारा पशुओं की उपस्थिति को सामान्य बना दिया है, जिसका सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पड़ रहा है। समाधान की आवश्यकता आवारा पशुओं को इस समस्या का

समाधान तुरंत किए जाने की जरूरत है। नगर निगम को सख्त कदम उठाने चाहिए और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए नियमित अभियान चलाने चाहिए। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जिससे यातायात सुचारू हो और दुर्घटनाओं में कमी आए। जब तक नगर निगम और प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते, फरीदाबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं का यह संकट बढ़ता रहेगा और लोगों की सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी।

2 अक्टूबर को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानें कहां और कैसे दिखाई देगा ?

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को होगा। यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण एक वलयाकार ग्रहण होगा।

इस बार पितृपक्ष पखवाड़े में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत जहां चंद्रग्रहण के साथ हुई है। पितृपक्ष पखवाड़े का समापन सूर्यग्रहण के साथ होगा। अच्छी बात यह है कि यह दोनों ही ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देंगे। दुनिया के अलग-अलग देशों में यह दिखेंगे। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि वैदिक पंचांग के अनुसार 02 अक्टूबर को आश्विन अमावस्या है। सनातन धर्म में आश्विन अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। आश्विन अमावस्या पर वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्यग्रहण लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण कंकण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। इस दौरान तीन ग्रहों पर राहु की सीधी दृष्टि रहने वाली है। बुध, केतु और सूर्य तीनों ग्रह इस दौरान कन्या राशि में बुध, केतु और सूर्य रहेंगे। राहु की सीधी दृष्टि इन सभी ग्रहों पर रहने वाली है।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि ज्योतिष के ग्रंथ बृहत्संहिता में ग्रहण के बारे में भविष्यवाणियों की गई हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि जब-जब एक ही महीने में दो ग्रहण एक साथ होते हैं, तब-तब दुनिया में हादसों की वजह से जनहानि होती है।

2 अक्टूबर को दूसरा सूर्य ग्रहण
ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को होगा। यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण एक वलयाकार ग्रहण होगा। यह तब होता है जब

पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा हो, लेकिन इसकी दूरी धरती से दूर हो। धरती से दूर होने के कारण चंद्रमा छोटा दिखता है। इस कारण यह इतना बड़ा नहीं होता कि पूरे सूर्य की किरणों को रोक ले। इस वजह इसके चारों ओर एक रिंग जैसी आकृति दिखाई देती है। इस सूर्य ग्रहण का ज्यादातर पथ प्रशांत में होगा। दक्षिण अफ्रीका के चिली और अर्जेंटीना में यह एकदम साफ दिखेगा।

सूर्य ग्रहण समय: 2 अक्टूबर की रात्रि 09:13 मिनट से मध्य रात्रि 03:17 मिनट पर समाप्त होगा
सूर्य ग्रहण की कुल अवधि: 6 घंटे 04 मिनट
साल 2024 में 4 ग्रहण
ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि साल 2024 में भी चार ग्रहण देखने को मिलेंगे। इनमें से दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण होंगे। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 होली के दिन लगा था। वहीं, दूसरा चंद्र ग्रहण बुधवार 18 सितंबर को लगेगा। इसके अलावा, पहला सूर्य ग्रहण सोमवार 8 अप्रैल को लगा था। दूसरा सूर्य ग्रहण बुधवार 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है। विशेष बात यह है कि दोनों ग्रहण के दिन समान ही हैं। यानी कि पहला चंद्र और सूर्य ग्रहण सोमवार को हैं। वहीं दूसरा चंद्र और सूर्य ग्रहण बुधवार को हैं।

कहां-कहां दिखेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण
भविष्यवाक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तरी-अमेरिका के दक्षिणी भागों, प्रशांत महासागर, एटलांटिक महासागर और न्यूजीलैंड, फिजी आदि देशों में कुछ समय के लिए दिखाई देगा। दिखाई देने वाले मुख्य देश होंगे- चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड और फिजी में हालांकि, यहां भी बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। इस ग्रहण की कंकण कृति केवल दक्षिणी चिली और दक्षिणी अर्जेंटीना में ही दिखाई देगी।

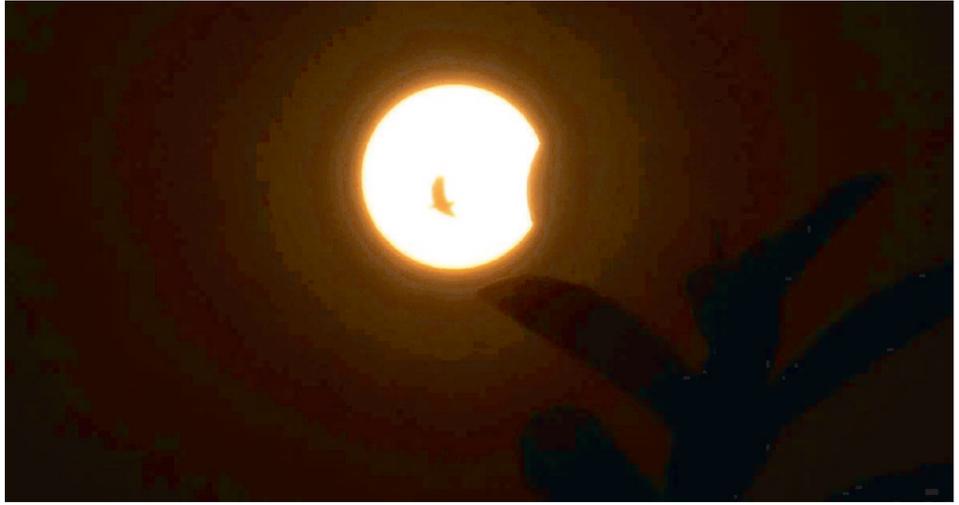
भारत में मान्य नहीं होगा सूतक काल
कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया

कि सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले इसका सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण लगने के बाद तक रहता है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए यहां पर इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा।

क्या होता है कंकण सूर्य ग्रहण
भविष्यवाक्ता डा. अनीष व्यास ने बताया कि जब धरती से ठीक एक लाइन में सूर्य, चंद्रमा आ जाते हैं। यानी राहु और केतु पर ना होकर ऊंचे या नीचे होते हैं। तब उसकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती और बिंब छोटे दिखाई देते हैं। जिसकी वजह से सूर्य का मध्य भाग ढक जाता है और उसके चारों तरफ से रोशनी दिखाई देती है लेकिन, इसका मध्य भाग ढक जाता है। इस प्रकार के ग्रहण को कंकण सूर्यग्रहण कहते हैं। जिसने सूर्य कंगन के समान नजर आने लगता है।

2022 में दो ग्रहण का योग
भविष्यवाक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि साल 2022 में सिर्फ 15 दिन के अंतराल में ही दो ग्रहण लगे थे। 1979 में 22 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 6 सितंबर को चंद्र ग्रहण हुआ था। ठीक ऐसा ही योग 2022 में भी बना। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था और अब 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण था। रविवार 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर बना स्पेशन ब्रिज टूट गया। उस समय पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे, जो नदी में जा गिरे। इस हादसे में 190 लोगों की मौत हो गई। साल 2022 से पहले 1979 में भी मच्छु नदी का डैम टूटने से हादसा हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 2022 और 1979 के इन दोनों हादसों में एक बात कॉमन है कि उस समय भी सूर्य और चंद्र ग्रहण हुए थे।

1979 में भी हुए थे ऐसे ही हादसे
भविष्यवाक्ता डा. अनीष व्यास ने बताया कि 43 साल पहले 11 अगस्त 1979 को भी मोरबी में डैम टूटने से बाढ़ आ गई थी और हजारों लोग मारे गए थे। उस साल 22 अगस्त को सिंह राशि में सूर्य ग्रहण हुआ था। इसके बाद 6 सितंबर को कुंभ राशि में चंद्र



ग्रहण हुआ था। अक्टूबर-1979 में फिलीपींस में तूफान आया था, जिसमें बड़ी जनहानि हुई थी। ठीक ऐसे ही हादसे 2022 में भी हो रहे हैं।

बृहत्संहिता के अनुसार दो ग्रहणों का असर
कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ बृहत्संहिता के राहुचाराध्याय में लिखा है कि जब दो-दो ग्रहण एक साथ एक ही महीने में होते हैं तो तूफान, भूकंप, मानवीय भूल से बड़ी संख्या में जनहानि होने के योग बनते हैं। एक ही महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं तो सेनाओं की हलचल बढ़ती है। सरकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा आने के योग रहते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं की आशंका
भविष्यवाक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के साथ अग्नि कांड भूकंप गैस दुर्घटना वायुयान दुर्घटना

होने की संभावना। पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता यानि राजनीतिक माहौल उच्च होगा। पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो जायेगा। रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होगी। आय में बढ़ोतरी होगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ रहेगा। खाने की चीजों की कीमतें सामान्य रहेंगी। दुर्घटनाएं आगजनी आतंक और तनाव होने की संभावना। ऑटोमोबाइल धरना प्रदर्शन हड़ताल, बैंक चोटाला, वायुयान दुर्घटना, विमान में खराबी, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव होगा। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ज्यादा होंगे। सत्ता संगठन में बदलाव होंगे। मनोरंजन फिल्म खेलकूद एवं गायन क्षेत्र से बुरी खबर मिलेगी। बड़े नेताओं का दुखद समाचार मिलने की संभावना।

अगले सूर्य ग्रहण की तारीख
29 मार्च 2025: यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यूरोप, एशिया के कुछ हिस्से, अफ्रीका, उत्तरी

अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर में दिखेगा।

21 सितंबर 2025: यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में दिखेगा।

17 फरवरी 2026: यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो अंटार्कटिका में दिखेगा। इसके अलावा आंशिक ग्रहण अंटार्कटिका के अन्य हिस्से, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा।

12 अगस्त 2026: यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में दिखेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा।

हाई ब्लड प्रेशर के इन लक्षणों को नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

अधिकांश समय, उच्च रक्तचाप के कारण सिरदर्द या नाक से खून नहीं आता है। लेकिन, यह यह समस्या तब हो सकती है जब रक्तचाप 180/120 से ऊपर हो। यदि आपका रक्तचाप बहुत अधिक है और आपको ये लक्षण हैं, तो 5 मिनट आराम करें और फिर से जांच करें। उच्च रक्तचाप के बारे में सबसे खतरनाक चीज यह है कि अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती है कि वह हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च रक्तचाप के कोई लक्षण नहीं होते हैं जब तक कि यह बहुत गंभीर न हो। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को समय-समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो घर पर भी रक्तचाप पर नजर रख सकते हैं। हालांकि, कुछ स्थितियों में हाई ब्लड प्रेशर होने पर व्यक्ति को कुछ लक्षण नजर आ सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको रक्तचाप से जुड़े ऐसे ही लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए-

- नकसीर
 - थकान
 - नजरो की समस्या
 - छाती में दर्द
 - सांस लेने में दिक्कत
 - दिल की अनियमित धड़कन
 - पेशाब में खून आना
- अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आपको उच्च रक्तचाप से ग्रस्त संकट हो सकता है जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। आपको एक और गंभीर स्वास्थ्य स्थिति भी हो सकती है। अधिकांश समय, उच्च रक्तचाप के कारण सिरदर्द या नाक से खून नहीं आता है। लेकिन, यह यह समस्या तब हो सकती है जब रक्तचाप 180/120 से ऊपर हो। यदि आपका रक्तचाप बहुत अधिक है और आपको ये लक्षण हैं, तो 5 मिनट आराम करें और फिर से जांच करें। यदि आपका रक्तचाप अभी भी असामान्य रूप से उच्च है, तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह भी याद रखें कि उच्च रक्तचाप में आमतौर पर लक्षण नहीं होते हैं। इसलिए सभी को इसकी नियमित जांच करानी चाहिए।



घर पर आसानी से बनाएं ढाबे स्टाइल पनीर की सब्जी

सबसे पहले पनीर को बड़े टुकड़ों में या बड़े क्यूब्स में काट लें। अब इसमें तेल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और पानी डालें। सभी तरफ से कोट करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं और इसे 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें।

नौर एक ऐसा व्यंजन है, जिसे अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर, इसे घर में कई तरह से बनाया जाता है। यहां तक कि, अगर घर में कोई मेहमान भी आने वाला होता है तो लोग पनीर अवश्य बनाते हैं। आपने भी अपने घर में पनीर की सब्जी को कई बार बनाया होगा। लेकिन अगर आपको वह स्वाद नहीं मिलता है, जो ढाबे की पनीर की सब्जी में होता है तो ऐसे में अब आपको इसे एक अलग अंदाज में बनाना चाहिए। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको पनीर मसाला बनाने की ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानने के बाद हर कोई आपके कुकिंग स्किल्स की तारीफ करेगा-

- आवश्यक सामग्री-**
पनीर को मैरिनेट और फ्राई करने के लिए
- 15 बड़े पनीर क्यूब्स 250 से 300 ग्राम लगभग
- 1 छोटा चम्मच तेल मैरिनेशन के लिये
 - 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
 - 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
 - 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर
 - 1/2 छोटा चम्मच चूनी
 - 1 बड़ा चम्मच पानी
 - 1 छोटा चम्मच तेल तलने के लिये
 - 1 छोटा चम्मच मक्खन तलने के लिये
- टैपरिंग के लिए**
- 4 बड़े चम्मच तेल
 - 2 चम्मच मक्खन
 - 3 छोटे तेज पत्ते
 - 1 छोटा चम्मच जीरा



- 3 छोटी सूखी लाल मिर्च
 - 3 छोटी हरी मिर्च
- सॉट करने के लिए**
- 1.5 कप प्याज छोटा हुआ
 - 1 टेबल-स्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट
 - 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
 - 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
 - 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर
 - 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर
 - 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
 - 1 टेबल स्पून बेसन
 - 2 कप टमाटर प्यूरी
 - 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर
 - 1/2 छोटा चम्मच चीनी
 - 1.5 चम्मच नमक
 - 2 चम्मच कसूरी मेथी
 - 1 कप पानी
 - 1/4 कप धनिया पत्ती

बनाने का तरीका-
सबसे पहले पनीर को बड़े टुकड़ों में या बड़े क्यूब्स में काट लें। अब इसमें तेल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और पानी डालें। सभी तरफ से कोट करने के लिए अच्छी तरह मिलाएं और इसे 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। अब एक गहरे फ्राई पैन में तेल और थोड़ा मक्खन गरम करें। तेज पता, जीरा, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च के साथ तड़का लगाएं। इसे कुछ सेकंड के लिए पकाएं। अब इसमें एक चुटकी नमक के साथ कीमा बनाया हुआ प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। एक बार जब यह हल्का सुनहरा हो जाए, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ मिनट के लिए भूनें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, बेसन, नमक और आधा कसूरी मेथी के पत्ते डालें। प्याज के मिश्रण को सभी मसाला

पाउडर के साथ भूरा होने तक भूनें और एक सूखा गाढ़ा मसाला बन जाए। अब टमाटर प्यूरी के साथ गरम मसाला पाउडर, नमक और चीनी डालें। अब हरी मिर्च डालें और बाकी सूखी मेथी डालें। ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। जब टमाटर की प्यूरी पक जाए और गाढ़ी हो जाए, प्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा पानी डालें। अब एक दूसरे फ्राइंग पैन में तेल और थोड़ा मक्खन गरम करें। पनीर क्यूब्स रखें और एक दो मिनट के लिए शौलो फ्राई करें और बंद कर दें। इसे अलग रख दें। ध्यान दें कि इसे ज्यादा देर तक न तलें, इससे पनीर रबड़ जैसा हो जाएगा। अब तले हुए पनीर को तैयार प्रेवी में डालें और ढककर तब तक पकाएं जब तक कि ऊपर से तेल अलग न हो जाए। अंत में धनिया पत्ती से गार्निश करें। इसके ऊपर कुछ ताजी मलाई या क्रीम डालें। हालांकि, यह पूरी तरह से वैकल्पिक है।

20 सितंबर से पहले कर लें ये काम, नहीं तो कहीं हो ना जाए आपका जीमेल अकाउंट बंद, जानें पूरी जानकारी...

अगर आपने कई दिनों से अपना गूगल जीमेल या गूगल अकाउंट यूज नहीं किया है तो ये रिस्क में है। गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए एक नियम किफ है। कंपनी इनएक्टिव अकाउंट को डिलीट कर अपने सर्वर स्पेस को फ्री करना चाहती है।...



गूगल 20 सितंबर को लाखों जीमेल अकाउंट बंद करने जा रहा है। अगर आपने कई दिनों से अपना गूगल जीमेल या गूगल अकाउंट यूज नहीं किया है तो ये रिस्क में है। गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए एक नियम किफ है। कंपनी इनएक्टिव अकाउंट को डिलीट कर अपने सर्वर स्पेस को फ्री करना चाहती है।

Gmail अकाउंट डिलीट होने से ऐसे बचाएं ?
अगर आपका जीमेल अकाउंट काफी लंबे समय से एक्टिव नहीं तो गूगल इसे बंद कर सकता है। अकाउंट एक्टिवेट रखने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें।

जीमेल अकाउंट में लॉग इन कर आप अकाउंट डिलीट होने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही जीमेल के में आए मेल को ओपन करें या फिर किसी को मेल भेजकर भी आप अपना अकाउंट एक्टिवेट रख सकते हैं। गूगल सर्विसेज जैसे गूगल फोटोज, गूगल

ड्राइव को इस्तेमाल कर करके भी आप अपना जीमेल अकाउंट एक्टिवेट रख सकते हैं। यूट्यूब में वीडियो देखकर भी आप अपना जीमेल अकाउंट एक्टिवेट रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जीमेल से यूट्यूब पर लॉगइन करना होगा। इतना ही नहीं गूगल पर सर्च करते हैं तो भी अपने अकाउंट को एक्टिवेट रख सकते हैं। वहीं गूगल का कहना है कि वे दो साल ने इनएक्टिव जीमेल अकाउंट को बंद करने जा रहा है। कई सारे यूजर्स गूगल पर मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं। इनमें से ज्यादातर अकाउंट यूजर्स लंबे समय से यूज नहीं करते हैं। ऐसे में कंपनी के सर्वर में काफी स्पेस बिना वजह भरा रहता है। इसे मैनेज करने के लिए कंपनी समय समय पर इनएक्टिव अकाउंट को डिलीट करते रहती है। गूगल का कहना है कि वह ऐसे जीमेल अकाउंट जो दो साल या उससे पहले से इस्तेमाल में नहीं हैं। उन्हें डिलीट करेगी। गूगल ऐसे यूजर्स को नोटिफिकेशन भी भेज रही है और अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए अपील भी कर रही है।

गाजियाबाद में 10 हजार युवाओं को मिली नौकरी, सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

Ghaziabad Rojgar Mela 2024 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और उद्यमियों को लोन वितरण कार्यक्रम के दौरान चेक सौंपे। रोजगार मेले में अधिकांश ऐसे युवा पहुंचे जिन्होंने इसी वर्ष योग्यता का डिप्लोमा पूरा किया है। बारिश और कीचड़ की बाधा पार कर पहुंचे युवाओं के चेहरे रोजगार पाकर खिल उठे।

गाजियाबाद। मौका था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित वृहद रोजगार मेले का। रोजगार मेले में 100 से अधिक निजी कंपनियों ने स्टॉल लगाए थे। बुधवार सुबह से हो रही बारिश और कीचड़ की बाधाओं को पार करते हुए हजारों युवाओं का वृहद रोजगार मेले में निजी कंपनियों ने साक्षात्कार लिया। योग्यता के आधार पर मौके पर करीब 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृहद रोजगार मेले में

पहुंचे और निजी कंपनियों की ओर से लगाए गए स्टॉल में पहुंचे। उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के बारे में जानकारी ली।

योग्यता के आधार पर मिली नौकरी

उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक युवा को उसकी योग्यता के आधार पर उसकी पसंद का रोजगार प्रदान कर रहे हैं। भविष्य में उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपना प्रदेश छोड़ अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। युवाओं को उनके लिए गृह जनपद में ही रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। कंपनियों की ओर से अपने-अपने स्टॉल के बाहर युवाओं की शिक्षा और दक्षता के आधार पर रिक्रियता बोर्ड पर दर्शायी गई थी।

रोजगार हासिल करने के लिए युवाओं ने सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। शिक्षा और योग्यता के आधार पर युवाओं की भीड़ सभी स्टॉल के बाहर रिक्रियता तलाशती रहीं। अपने अनुरूप नौकरी की रिक्रियता देखने के बाद कंपनियों से साक्षात्कार के लिए फार्म लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

मौके पर 11 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। साक्षात्कार में खरा उतरने के बाद कंपनियों की ओर से युवाओं को हाथों हाथ नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

327 करोड़ का लोन बांटा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 632 लाभार्थियों को रुपये 327 करोड़ रुपये का लोन वितरित किया गया। उन्होंने कहा प्रदेश के युवाओं के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाकर स्वरोजगार के साथ ही दूसरे युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया जाएगा। सात लाभार्थियों को मंच से चेक वितरित किए गए। इनमें उद्यमियों को 30 करोड़ से लेकर स्वनिधि योजना के तहत 20 हजार रुपये तक के चेक शामिल रहे।

दूसरे चरण में दिया जाएगा 10 लाख रुपये का लोन

अर्थव्यवस्था में यूपी अब देश में 10वें से दूसरे स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ की जाएगी, जिसके प्रथम चरण में बिना ब्याज पांच लाख और द्वितीय चरण में 10 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। उन्होंने

कहा 10 वर्ष पूर्व यूपी अर्थव्यवस्था में देश में 10वें स्थान पर था, जो आज दूसरे स्थान पर है। जल्द ही उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर होगा।

पंजीकरण के लिए लगाए गए 20 स्टॉल

वृहद रोजगार मेले में पहुंचे बहुत से युवाओं का पंजीकरण नहीं था, लेकिन उनके लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों की ओर से हेल्प डेस्क और पंजीकरण काउंटर लगाए गए थे। यहां पंजीकरण करने के लिए काफी संख्या में युवाओं की भीड़ रही। दरअसल, पंजीकरण के लिए दिया गया बार कोड दो दिन से तकनीकी खराबी के चलते काम नहीं कर पाया। युवाओं ने सीधे रोजगार मेले में पहुंचकर पंजीकरण करवाया।

वाहन न मिलने पर भीगते रहे छात्र व अभ्यर्थी

मोबाइल, टेबलेट और नियुक्ति पत्र लेकर बारिश के बीच छात्र और अभ्यर्थी बाहर तो निकले, लेकिन वाहनों की तलाश में इधर-उधर खड़े भीगते रहे। दरअसल, मुख्यमंत्री के आगमन पर सभी रास्तों को ब्लाक किया गया था। इस कारण ई-रिक्शा, श्री व्हीलर व अन्य वाहन कार्यक्रम स्थल घंटाघर रामलीला मैदान मार्ग पर नहीं दिखे।



महज 26 साल में गृह राज्यमंत्री बन गए थे राव नरबीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह को दी थी पटखन

राव नरबीर सिंह हरियाणा की राजनीति में एक जाना-माना नाम हैं। मात्र 26 साल की उम्र में विधायक और गृह राज्यमंत्री बनने वाले राव नरबीर सिंह ने अपने राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। राव नरबीर सिंह 1987 में राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव में हराकर विधानसभा पहुंचे थे। आइए राव नरबीर सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। अहीरवाल की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले राव नरबीर सिंह मात्र 26 साल की उम्र में ही न केवल विधायक चुने गए थे बल्कि प्रदेश के गृह राज्यमंत्री बन गए थे। हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ताऊ के नाम से मशहूर चौधरी देवीलाल ने 1987 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अपनी सरकार में उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जगह दी थी।

राव का छोरा कुछ करेगा... दिया मंत्री पद

ताऊ देवीलाल ने यह कहते हुए मंत्री पद दिया था कि राव का छोरा कुछ करेगा। परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए देवीलाल ने अपने मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को शामिल किया था। वरिष्ठ भाजपा नेता राव नरबीर सिंह ने अपना पहला चुनाव जाटसाना से 1987 में लोकदल के टिकट पर लड़ा था।

उस चुनाव में उन्होंने अहीरवाल के दिग्गज राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले वर्तमान में गुडगांव से सांसद व केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह को हराया था।

राव इंद्रजीत की हार की हुई थी काफी चर्चा

राव इंद्रजीत सिंह की हार उस समय काफी चर्चा का विषय बना था क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अहीरवाल के राजा राव तुलाराम के वंशज हैं। यही नहीं हरियाणा की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी रहे पूर्व मुख्यमंत्री स्व. राव बीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं। राव बीरेंद्र सिंह केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे थे।

इस जीत से राव नरबीर सिंह ने उस समय लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी देवीलाल सहित सभी दिग्गजों को अपना दीवाना बना लिया था। उम्र केवल 26 साल होने की वजह से सभी नेता स्नेह देते थे। चौधरी देवीलाल हर जगह यही कहा करते थे कि राव का छोरा कुछ करेगा।

तीन बार विधायक रहे राव नरबीर सिंह के पिता

दरअसल, राव नरबीर सिंह के पिता स्व. राव महाबीर सिंह तीन बार विधायक रहे। वह प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। उनके चौधरी देवीलाल के साथ बेहतर संबंध थे। राव नरबीर सिंह के दादा राव मोहर सिंह आजादी से पहले 1942 एवं 1946 में पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे।

इस वजह से आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक के काफी नेताओं से राव



नरबीर सिंह के परिवार का संबंध रहा। जब 1996 में प्रदेश में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बंसीलाल ने भी राव नरबीर सिंह को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी।

1996 में सोहना से विधायक चुने गए थे राव नरबीर सिंह

उन्होंने उन्हें परिवहन, खाद्य आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्री बनाया था। 1996 में राव नरबीर सिंह सोहना से विधायक चुने गए थे।

सिस्टम की लापरवाही सांसों पर भारी, गाजियाबाद में पांच साल में केवल 52 दिन मिली शुद्ध हवा



पिछले पांच सालों में गाजियाबाद में केवल 52 दिन ही साफ हवा मिली है। बाकी दिनों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक मध्यम खराब बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में रही है। गंभीर श्रेणी की हवा मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इस श्रेणी की हवा में सांस व दमा के मरीजों को सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है।

साहिबाबाद। सिस्टम की लापरवाही से वायु प्रदूषण लोगों की सांसों पर वार कर रहा है। तमाम योजनाओं के दावे के बाद भी अधिकारी प्रदूषण रोकने में फेल साबित हो रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बीते करीब चार वर्ष, आठ माह में केवल 52 दिन ही साफ हवा मिल सकी। बाकी दिन लोग शुद्ध हवा के लिए तरसे रहे।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय अधिकारियों ने वर्ष 2020 से लेकर अगस्त 2024 तक यानी बीते 1705 दिन की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के अनुसार, कुल दिनों के सापेक्ष लोगों को तीन प्रतिशत दिन ही साफ हवा मिल सकी। बाकी दिन लोगों को संतोषजनक, मध्यम,

खराब, बेहद खराब व गंभीर श्रेणी की हवा में ही रहना पड़ा। सबसे अधिक 609 दिन हवा मध्यम श्रेणी में रही। इसके बाद 449 दिन लोगों को खराब व 277 दिन बेहद खराब हवा में रहना पड़ा।

वर्ष 2020 व 2021 में सबसे ज्यादा गंभीर श्रेणी में रही हवा

बीते पांच वर्ष की तुलना करते तो वर्ष 2020 व 2021 में हवा सबसे ज्यादा दिन गंभीर श्रेणी में रही है। वर्ष 2020 में 24 दिन तो वर्ष 2021 में 22 दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही। गंभीर श्रेणी की हवा मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इस श्रेणी की हवा में सांस व दमा के मरीजों को सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है।

हॉटस्पॉट से भी नहीं रुका प्रदूषण

बीते पांच वर्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बहुत प्रदूषण को रोकथाम के लिए सर्वे कर सात हॉटस्पॉट निर्दिष्ट किए थे। सर्वे साहिबाबाद, राजनगर एक्सप्रेसवे, लोनी, भोपुरा-दिल्ली बार्डर, साउथ साइड जोटी रोड, संजय नगर व सिद्धार्थ विहार अधिक प्रदूषित क्षेत्र पाए गए थे। अधिकारियों का दावा था कि इन इलाकों में कारवाइ कर प्रदूषण रोक जा रहा है।

सिर्फ कानून बनाने से नहीं रुकेंगे महिला अपराध

योगेन्द्र योगी

अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। यह बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। इससे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक और 2020 में महाराष्ट्र शक्ति विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इन दोनों विधेयकों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के सभी तरह के मामलों में अनिवार्य फांसी का प्रावधान किया गया था। इन दोनों विधेयकों को राज्य विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से पारित किया था। लेकिन दोनों विधेयकों अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ-साथ 2012 के पोक्सो अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीड़िता की उम्र चाहे जो हो, कई तरह के यौन उत्पीड़न के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। बीते महीने लागू हुए बीएनएस की धारा-64 में बलात्कार के लिए 16 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं बीएनएस की धारा-66 में बलात्कार और हत्या और ऐसे बलात्कार जिनमें पीड़ित निरक्षर हो जाती है, उनमें मौत की सजा का प्रावधान है। इसमें 20 साल की जेल की या उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

देश के नेताओं ने समस्याओं का आसान रास्ता तलाश कर रखा है। जब भी किसी समस्या से सामना हो तो कानून बना कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। समस्या की जड़ तक कोई भी राजनीतिक दल और सरकारें नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, किन्तु वहां तक पहुंचने और व्यवहारिक समाधान ढूँढ़ने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में वही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार करती रही हैं। मसलन कानून बना कर जिम्मेदारी पूरी कर लो। ममता सरकार ने विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए, और उन्हें पेरोल की सुविधा न दी जाए।

अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 शीर्षक वाले इस

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नये प्रावधानों के जरिये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। यह बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनसे पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। इससे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक और 2020 में महाराष्ट्र शक्ति विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इन दोनों विधेयकों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के सभी तरह के मामलों में अनिवार्य फांसी का प्रावधान किया गया था। इन दोनों विधेयकों को राज्य विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से पारित किया था। लेकिन दोनों विधेयकों अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ-साथ 2012 के पोक्सो अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीड़िता की उम्र चाहे जो हो, कई तरह के यौन उत्पीड़न के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। बीते महीने लागू हुए बीएनएस की धारा-64 में बलात्कार के लिए 16 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं बीएनएस की धारा-66 में बलात्कार और हत्या और ऐसे बलात्कार जिनमें पीड़ित निरक्षर हो जाती है, उनमें मौत की सजा का प्रावधान है। इसमें 20 साल की जेल की या उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी थी, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबदस्तती या असहमति से बनाए गए



संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था। लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। हालांकि, इन सबके बावजूद सुधार नहीं हुआ है। निर्भया कांड (2012) के बाद भारत में कई चर्चित बलात्कार की घटनाएँ हुई हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश के ही हाथरस जिले में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और अत्यंत बर्बरता की गई। पीड़िता की मृत्यु के बाद, उसके शव को

परिवार की अनुमति के बिना रात के समय दफनाया गया। मध्य प्रदेश के मुर्ना जिले में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई। पीड़िता की शिकायत के बावजूद, पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। हैदराबाद में एक महिला वेटरनरी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, और बाद में आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, जिसने विवाद और बहस को जन्म दिया। मणिपुर में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने हाल ही में बहुत ध्यान खींचा। इस मामले ने स्थानीय हिंसा और सामाजिक अस्थिरता को भी उजागर किया। साल 2013

में केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया, जिसका मकसद राज्यों को महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करना था। मगर, इसका अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। निर्भया फंड की 9 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। निर्भया फंड बनने से लेकर 2021-22 तक, कोष के तहत कुल आवंटन 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है, जिसमें से 4,200 करोड़ रुपये का ही अब तक इस्तेमाल हो पाया है।

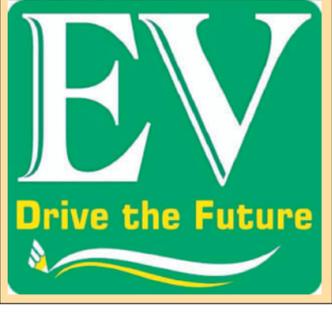
गौरतलब है कि भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में बलात्कार की एक घटना। देश में रेप के मामलों में 96 प्रतिशत से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों

में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। ये तीन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में न तो कमी आ रही है और न ही सजा की दर यानी कनिक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सालभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के चार लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं, बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं।

आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25 हजार मामले दर्ज किए जाते थे। लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30 हजार के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39 हजार के करीब पहुंच गया था। साल 2022 में औसतन हर दिन करीब रेप के 87 मामले दर्ज किए गए। इसी साल 248 रेप या गैंगरेप के साथ हत्या। 31,516 रेप, 3,288 रेप के प्रयास और 83,344 मामले महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए हमले के दर्ज किए गए। इन आंकड़ों से जाहिर है कि निर्भया कांड के बाद भी देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की तस्वीर नहीं बदली है। दरअसल नेताओं और सरकारों के इरादों में कमी है। देश में महिलाओं की सामूहिक तरक्की, पर्याप्त शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और अन्य सुविधाओं में इजाफा नहीं होगा तब तक निर्भया जैसी घटनाओं पर सिवाए चीख-पुकार मचाने से कुछ नहीं होगा। यह सब करना सरकारों के लिए आसान नहीं है। इसलिए जब भी कोई वारदात होती है तब कानून में कुछ और धाराएं जोड़ कर सरकारें अपनी दायित्व की इतिश्री कर लेती हैं।

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



ल्यूमैक्स ग्रीनप्यूल एनर्जी सॉल्यूशंस में बहुलांश हिस्सेदारी करेगा हासिल

परिवहन विशेष न्यूज

ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसने ग्रीनप्यूल एनर्जी सॉल्यूशंस में अपने मीडिया शेयर धारकों से अज्ञात राशि में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ल्यूमैक्स ऑटो ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित अधिग्रहण से कंपनी को हरित और वैकल्पिक ईंधन क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी, जिसमें आने वाले वर्षों में मजबूत और त्वरित वृद्धि देखने को मिलेगी।

ग्रीनप्यूल मुख्य रूप से सीएनजी

और हाइड्रोजन ऑटोमोबाइल के लिए उच्च दबाव ईंधन वितरण और भंडारण प्रणालियों का आपूर्तिकर्ता है।

यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए आग और धुआं अलार्म, पहचान और दमन प्रणाली की आपूर्ति भी करता है। यह मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स सहित प्रमुख ओईएम के लिए आपूर्तिकर्ता है।

ल्यूमैक्स ऑटो के प्रमोटर डायरेक्टर दीपक जैन ने कहा, 'सीएनजी वाहन बाजार में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है, खासकर यात्री वाहन

खंड में, हम अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले समाधान देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने और वैकल्पिक ईंधन खंड में सिस्टम और घटकों के लिए उद्योग के अग्रणी बनने की कोशिश करेंगे।'

ग्रीनप्यूल के संस्थापक और सीईओ अक्षय कश्यप ने कहा कि इस सहयोग से दोनों हितधारकों के लिए जबरदस्त मूल्य मिलने और ऑटोमोटिव क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे स्वच्छ और अधिक टिकाऊ गतिशीलता समाधानों की ओर बदलाव होगा।



महिंद्रा ने सारथी अभियान के तहत ट्रक ड्राइवरों की बेटियों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की

परिवहन विशेष न्यूज

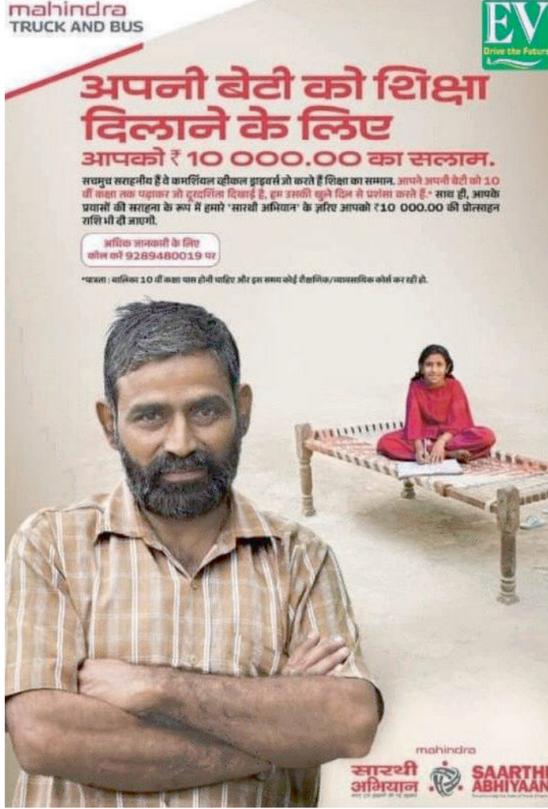
महिंद्रा समूह की इकाई महिंद्रा ट्रक एवं बस डिवीजन (एमटीबीडी) ने महिंद्रा सारथी अभियान के माध्यम से ट्रक चालकों की बेटियों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की।

चयनित उम्मीदवार को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह पूरे भारत में 75 से अधिक परिवहन केंद्रों पर एक पहुंच कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। 2014 में शुरू की गई इस पहल से अब तक 10,029 लड़कियों को लाभ हुआ है। यह सम्मान समारोह फरवरी से मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ट्रक, बस, सीई, एयरोस्पेस और रक्षा कारोबार के अध्यक्ष विनोद सहाय, महिंद्रा समूह के समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य ने कहा, 'महिंद्रा सारथी अभियान के माध्यम से, हम न केवल छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, बल्कि एक उज्ज्वल भविष्य के द्वार खोल रहे हैं और युवा दिलों में आशा का संचार कर रहे हैं। हम ट्रक चालक भागीदारों

की बेटियों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करके जीवन बदलने के लिए समर्पित हैं। उनके भविष्य में निवेश करके, हम सशक्त महिलाओं की एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो हमारे समुदायों और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के कमर्शियल वाहन बिजनेस हेड जलज गुप्ता ने कहा, 'महिंद्रा सारथी अभियान के जरिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता न सिर्फ ट्रक चालकों की बेटियों का उत्पादन करती है, बल्कि इस तरह हम उनके लिए नए अवसरों और नई प्रेरणा का माहौल भी बनाते हैं। इस पहल के माध्यम से हम कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में अधिक महिलाओं को देखना चाहते हैं। साथ ही हम उनके भविष्य में निवेश करने और एक मजबूत, अधिक न्यायसंगत समाज विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहना चाहते हैं, जहाँ हर लड़की अपनी क्षमता को पूरा करने और कल की नेता बनने की आकांक्षा रख सके।'



दक्षिण अफ्रीका के ऑटो क्षेत्र के लिए वाहन आयात का शीर्ष स्रोत बना भारत

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटोमोटिव बिजनेस काउंसिल ने अपनी ब्रिक्स+ रिसर्च रिपोर्ट 2024 में कहा है कि भारत 2013 से दक्षिण अफ्रीकी ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वाहन आयात का शीर्ष देश बन गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न ब्रांडों ने भारत को छोटे और प्रवेश स्तर के वाहनों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जिनकी घरेलू बाजार में बिक्री में बड़ी हिस्सेदारी है।

टाटा और महिंद्रा ने दक्षिण अफ्रीका में अपने ऑटोमोटिव उत्पादों को मजबूती से स्थापित किया है। महिंद्रा के अधिकारियों ने बार-बार दोहराया है कि दक्षिण अफ्रीका भारत के बाहर उनका दूसरा घर है क्योंकि उन्होंने डरबन में उत्पादन लाइन सहित बड़े निवेश किए हैं।

चीन और भारत 2010 से लगातार दक्षिण अफ्रीकी ऑटोमोटिव उद्योग के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ऑटोमोटिव आयात का बढ़ता स्तर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में प्रवेश करने वाले चीन ने 2022 से वाहन आयात के लिए दूसरे सबसे बड़े मूल देश के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, क्योंकि आर्थिक रूप से तंग उपभोक्ताओं ने घरेलू बाजार में अधिक किफायती मॉडल विकल्पों की ओर रुख किया है, जबकि देश 2018 से आफ्टरमार्केट पार्ट्स आयात के लिए शीर्ष मूल देश भी बन गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में, मोटर वाहन व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में भारी रूप से झुका हुआ रहेगा, जिसमें आयात-निर्यात मूल्य अनुपात 97.7:1 होगा, चीन के साथ 56.8:1 होगा तथा ब्राजील के साथ 2.6:1 होगा। इसमें मोटर वाहन व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों में पूरकताओं की खोज करने, अनुभवों को साझा करने तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों की आवश्यकता की पहचान की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में दक्षिण अफ्रीका के प्रवेश से देश



का अंतराष्ट्रीय कद बढ़ा है तथा इन प्रमुख आर्थिक ताकतों के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं।

2010 में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स में शामिल होने के बाद, 2010 से 2011 तक सभी चार भागीदार देशों के मोटर वाहन निर्यात में वृद्धि हुई, जिसका श्रेय उस समय दक्षिण अफ्रीकी मोटर वाहन उत्पादों में बढ़ती रुचि को दिया जा सकता है।

2010 से 2023 के बीच भारत के मामले में मोटर वाहन निर्यात में गिरावट आई है, जबकि ब्राजील, चीन और रूस के लिए, वृद्धि को दर्शाने के बावजूद, 2023 में घरेलू मोटर वाहन उद्योग के कुल रिकॉर्ड निर्यात राजस्व 270.8 बिलियन रैंड के संदर्भ में निर्यात नगण्य रहा।

रिपोर्ट में ब्रिक्स देशों से संबंधित इस उदासीन निर्यात प्रदर्शन के कारणों का हवाला देते हुए कहा गया है कि व्यापक बाजार और आर्थिक स्थितियां, ऑटोमोटिव नीतिगत कारक, टैरिफ उपाय और प्रासंगिक देश की प्रोफाइल दक्षिण अफ्रीका में निर्मित विशिष्ट प्रीमियम यात्री कार मॉडल और बेकी के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

जहां तक ऑटोमोटिव आयात का सवाल है, 2010 से

2011 के बीच चारों देशों से दक्षिण अफ्रीका में ऑटोमोटिव आयात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसमें कहा गया है कि 2010 से 2023 की अवधि में चीन, भारत और ब्राजील से ऑटोमोटिव आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में जनवरी 2024 से ब्रिक्स+ समूह में पांच और देशों के प्रवेश से दक्षिण अफ्रीका के लिए उत्पन्न होने वाले अवसरों को साझा किया गया।

1 जनवरी, 2024 से ब्रिक्स+ समूह में विस्तार, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, ऑटोमोटिव क्षेत्र सहित विभिन्न वैश्विक उद्योगों को नया आकार देने का वादा करता है।

नए सदस्य देशों के एकीकरण से ब्रिक्स+ के भीतर ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखलाओं का अनुकूलन हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिक्स संभावित सदस्यों के एक विविध समूह को आकर्षित करता है क्योंकि इसकी प्राथमिक-संचालित साझा इच्छा एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक परिदृश्य बनाने की है, जिसके बारे में कई देशों का मानना है कि वर्तमान में यह उनके खिलाफ पक्षपाती है।

तेजी से बढ़ रही भारत की ऑटो इंडस्ट्री, क्या चीन और अमेरिका को छोड़ पाएगी पीछे?



परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि अगले पांच साल में भारत की लाजिस्टिक लागत (माल ढुलाई लागत) एक अंक में आ जाएगी। 'डेल्टा गवर्नमेंट समिष्ट' को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि मंत्रालय कई राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत की लाजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी।

ऑटोमोबाइल उद्योग को नंबर एक बनाना लक्ष्य आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीपीईआर) के अनुमानों के अनुसार, भारत में

लाजिस्टिक्स लागत 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 7.8 प्रतिशत से 8.9 प्रतिशत के बीच थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने आगे कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है।

भारत जापान को हमने पीछे छोड़ा

उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया था। अब वह केवल अमेरिका और चीन से पीछे है। उनके अनुसार, भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 2014 में 7.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भारत की व्यापक

अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

निर्यात को कम करने की जरूरत

उन्होंने आगे कहा कि अगर हम किसानों की क्रय शक्ति बढ़ा सकते हैं, तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को अपने निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने की जरूरत है। स्मार्ट शहरों की तरह, स्मार्ट गांव भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। मंत्री ने कहा कि किसी भी संगठन में, वित्तीय आडिट की तुलना में प्रदर्शन आडिट अधिक महत्वपूर्ण है।

कंबोडिया ने 2050 तक 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कारों, 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक मोटरबाइकों का लक्ष्य रखा है: मंत्री



नई दिल्ली। लोक निर्माण और परिवहन मंत्री पेंग पोनिया ने बुधवार, 18 सितंबर को कहा कि कंबोडिया कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2050 तक 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक कारों और 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों 2024-2030 के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति पर एक प्रसार कार्यशाला के दौरान यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, 'ईवी क्षेत्र उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि इसने न केवल पर्यावरण को बढ़ाया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि आर्थिक आधार विविधीकरण की गति के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत किया है।'

उन्होंने कहा, 'ईवी के उपयोग ने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।'

कंबोडिया में वर्तमान में 7 मिलियन से अधिक पेट्रोल चालित वाहन हैं, उन्होंने कहा, उनमें से 85 प्रतिशत मोटरसाइकिलें थीं, 10 प्रतिशत कारें थीं, और पांच प्रतिशत बसें, लॉरी और भारी मशीनरी थीं।

पोनिया ने कहा कि आज तक, दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने कुल 3,676 ईवी पंजीकृत किए हैं, और राज्य में 21 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं।

लोक निर्माण और परिवहन मंत्रालय के अनुसार, कंबोडिया में तीन सबसे लोकप्रिय ईवी ब्रांड चीन के बीवाईडी, जापान के टोयोटा और अमेरिका के टेस्ला हैं।

भारत में लिथियम-आयन बैटरी बनाने की क्षमता है, कश्मीर में वैश्विक लिथियम स्टॉक का 6% है: नितिन गडकरी

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार, 17 सितंबर को कहा कि जम्मू-कश्मीर में दुनिया के लिथियम स्टॉक का 6 प्रतिशत हिस्सा है और भारत में लिथियम-आयन बैटरी बनाने की क्षमता है। यह टिप्पणी रिवोल्ट मोटर्स द्वारा ईवी बाइक के लॉन्च इवेंट में की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ओला जल्द ही देश में लिथियम-आयन बैटरी का उत्पादन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि लिथियम-आयन बैटरी की कीमत 150 रुपये प्रति किलोवाट थी, जो अब घटकर 105 रुपये हो गई है और दो साल के भीतर यह और कम हो जाएगी।

भारत की निर्यात क्षमता के बारे में नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले वाहनों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईवी दोपहिया वाहनों को बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफ्रीकी देशों में निर्यात किया जा सकता है। बजाज और हीरो के नेतृत्व में भारत वर्तमान में अपने दोपहिया वाहनों का 50 प्रतिशत निर्यात करता है।

उन्होंने कहा कि ईवी बाजार का भविष्य उज्ज्वल है और देश का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में दुनिया का अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता बनना है। उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए अच्छी गुणवत्ता, कम रखरखाव और सही तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण है।

गडकरी ने कहा, 'इंधनवरी, गुणवत्ता और विश्वसनीयता 21वीं सदी की सबसे बड़ी पूंजी है। ज्ञान और कचरे को संपदा में बदलना ही भविष्य है।'

उन्होंने कंपनियों से स्ट्रैपिंग प्लांट लगाने का भी आग्रह किया ताकि रीसाइक्लिंग के जरिए उत्पादन लागत कम हो और गुणवत्ता से समझौता किए बिना उत्पादों की कीमत 30 फीसदी कम हो।

अपने संबोधन के दौरान गडकरी ने प्रदूषण कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने वैकल्पिक ईंधन और ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके वाहन बनाने की भारत की क्षमता पर जोर दिया।

गडकरी ने कहा, 'रूईडन ऑयल ने चावल के भूसे से 1 लाख करोड़ लीटर इथेनॉल और 88,000 टन बायो-

एविएशन ईंधन बनाने की परियोजना शुरू की है। बायो ईंधन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गन्ना, मक्का, बांस और चावल के भूसे से इथेनॉल के उत्पादन के लिए शोध शुरू किया गया है।

उन्होंने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताया और कहा कि अगर इसे नग्न निगम के कचरे से बनाया जाए तो यह सस्ता हो सकता है। गडकरी ने कहा, '1 किलो हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए 50 यूनिट बिजली की जरूरत होती है, इसलिए जैविक कचरा ही आगे का रास्ता है।'

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में बात की और कहा कि पिछले दशक में यह 7 लाख करोड़ रुपये के उद्योग से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये का बाजार बन गया है, जिससे यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। गडकरी ने कहा कि इस क्षेत्र में अधिकतम निर्यात और जीएसटी संग्रह में योगदान दिया है। उन्होंने कहा, 'दोपहिया उद्योग की 50 प्रतिशत आय निर्यात से आती है।'



फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में क्यों की कटौती, क्या अब टल जाएगा मंदी का खतरा?

परिवहन विशेष न्यूज

US Fed Rate Cut फेड रिजर्व ने चार साल में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। अमेरिका में आर्थिक आंकड़े काफी समय से सुस्त थे। रोजगार के मोर्चे पर भी स्थिति खराब थी। कुल मिलाकर मंदी आने के सभी संकेत सामने थे। इससे फेड रिजर्व को ब्याज दरों में बड़ी कटौती करनी पड़ी। आइए जानते हैं कि क्या ब्याज दरों में कटौती से मंदी का खतरा टल गया?

नई दिल्ली। दुनियाभर को जैसी उम्मीद थी, बुधवार करीब आधी रात को वही हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट या फिर कहें कि 0.50 फीसदी (US Federal Rate Cut) की कटौती की। यह पिछले साल यानी कोरोना महामारी के बाद पहली दफा है, जब अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कमी की है। इसका मकसद मंदी की आशंका से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

बेशक फेड रिजर्व की कटौती काफी बड़ी है, लेकिन इसका अमेरिकी शेयर बाजार ने कोई खास इस्तकबाल नहीं किया। वहां के तीनों प्रमुख इंडेक्स- Dow Jones, Nasdaq Composite और S&P 500 में रेट कट के बाद थोड़ी तेजी दिखाई। लेकिन, आखिर में तीनों गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि, भारत समेत अन्य एशियाई में जरूर उछाल दिखा। लेकिन, भारत में मिड और स्मॉल कैप में भारी गिरावट आई है। कुछ हैवीवेट लाज कैप ने मार्केट को थोड़ा सहारा दिया है।

आइए जानते हैं कि ब्याज दरों में भारी कटौती के बावजूद अमेरिकी निवेशकों का भरोसा बहाल क्यों नहीं हुआ? क्या अमेरिका में अभी भी मंदी का

खतरा है और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के भारत के लिए क्या मायने नहीं है?

अमेरिकी निवेशकों में अनिश्चितता क्यों अमेरिका में आर्थिक आंकड़े काफी समय से सुस्त थे। खासकर, बेरोजगारी के। कई वरिष्ठ अर्थशास्त्री लंबे वक्त से ब्याज दरें घटाने की मांग कर रहे थे। खुद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने दरों में कटौती के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि ब्याज दरें घटाने में कुछ देरी हुई। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ब्याज दरों में आने वाले समय में भी कटौती हो सकती है। यह काफी हद तक मुद्रास्फीति और दूसरे आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

यही वजह है कि ब्याज दरों में कटौती का अमेरिकी शेयर मार्केट पर फौरन सकारात्मक असर नहीं दिखा। दरअसल, निवेशकों के हिसाब से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत काफी पहले से हो जानी चाहिए थी। इससे अब तक ब्याज दरें 1 फीसदी तक कम हो गई होतीं। यही वजह है कि अमेरिकी शेयर बाजार ने उस तरीके का उत्साह नहीं दिखाया, जैसी उम्मीद थी। यहां तक कि भारत में मिड और स्मॉल कैप ध्वस्त होते दिखे।

क्या मंदी का खतरा टल गया?

अमेरिका में आर्थिक मंदी का जो खतरा है, उसका अंदाजा हर किसी को था। दरअसल, अमेरिका में कोरोना के बाद मुद्रास्फीति काफी तेजी से बढ़ रही थी। इस पर लगातार लगाते के लिए अमेरिका ने ब्याज दरों में सिलसिलेवार इजाफे का रास्ता अपनाया। उससे जाहिर था कि आखिरकार आर्थिक मंदी आएगी, जिसके चलते नौकरियां जाएंगी। हालांकि, अभी तक अमेरिका में आर्थिक मंदी आई नहीं है। फेडरल रिजर्व ने डैमेज कंट्रोल के तहत ब्याज दरों में कटौती करनी शुरू कर दी और यह सिलसिला अर्थव्यवस्था की सहेत सुधारने तक जारी रहने की उम्मीद है।

अब फेड रिजर्व के सामने चुनौती है कि वह इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग कराए। इसका मतलब है कि आर्थिक और नौकरियों के मोर्चे पर ज्यादा नुकसान हुए बिना इकोनॉमी को पटरी पर लाना। साथ ही, मुद्रास्फीति से भी तालमेल बिठाना होगा कि उसमें यकायक तेज उछाल न आ जाए। हालांकि, जेरोम पोवेल ने भरोसा दिलाया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मूलरूप से ठीक है। इस साल फेड रिजर्व ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की और कटौती कर सकता है।

ब्याज दरों में कटौती का असर क्या होगा?

ब्याज दरों में कटौती का अमूमन शेयर मार्केट और गोल्ड पर सबसे पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि इन चीजों में रिटर्न ब्याज दरों में कटौती से प्रभावित नहीं होता। वहीं, बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड जैसे निवेश का रिटर्न घट सकता है। इससे आम जनता को भी फायदा होता है, क्योंकि होम लोन, कार लोन सस्ते हो जाते हैं। अमेरिका में कार लोन फ्रिलहाल 2001 के बाद से अपनी सबसे महंगी दर पर है। अब कंपनियों को भी सस्ती दर पर कर्ज मिलेगा, इससे वे भी रोजगार के मोके बढ़ा सकती हैं।

अमेरिका में कटौती से भारत जैसे देशों में भी ब्याज दर सस्ता करने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, अभी आरबीआई का अभी पूरा ध्यान



टल गया मंदी का खतरा?

महंगाई कम करने पर है। आरबीआई गवर्नर ने पिछले दिनों संकेत भी दिया था कि भारत की रेट कट की नीति दूसरे देशों के हिसाब से नहीं चलेगी। लेकिन, मान जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत तक ब्याज दरों में कटौती कर सकती है।

ब्याज कटौती पर एक्सपर्ट की क्या राय है? नीतिगत दरों में मौजूदा कटौती को लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि सस्ता लोन से भारत में निवेश प्रवाह को बढ़ावा

देगा, जबकि बाकियों का कहना है कि इससे इक्विटी पर रिटर्न में कमी आ सकती है और सोने में भी ब्याज दरों में कटौती की जमीन तैयार होगी। बिज2क्रेडिट और बिज2एक्स के को-फाउंडर और सीईओ रोहित अरोड़ा ने कहा, 'इससे भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा और रुपया मजबूत होगा। इससे भविष्य में आरबीआई को ब्याज दरें कम करने का मौका मिलेगा।'

वहीं कामा ज्वेलरी के एमडी कालिन शाह का कहना है कि गोल्ड इंडस्ट्री के लिए ब्याज दरों में कटौती सकारात्मक है। इसने सोने के लिए जल्द

ही नहीं कंचाइयों को छुने के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे सोने में निवेश बढ़ेगा। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दरों में कटौती से उभरते बाजारों में भी ब्याज दरों में कटौती की जमीन तैयार होगी। बिज2क्रेडिट और बिज2एक्स के को-फाउंडर और सीईओ रोहित अरोड़ा ने कहा, 'इससे भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा और रुपया मजबूत होगा। इससे भविष्य में आरबीआई को ब्याज दरें कम करने का मौका मिलेगा।'

बजाज हाउसिंग फ़ाइनेंस में भारी गिरावट, शेयर बेचकर क्यों भाग रहे निवेशक?

बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर की कीमत बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लिस्टिंग के बाद से लगातार चर्चा है। इसने निवेशकों को 114 फीसदी का बंपर लिस्टिंग गेन दिया। उसके बाद भी लगातार अपर सर्किट लगे। हालांकि अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मुनाफावसूली हावी हो गई है।

नई दिल्ली। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 16 सितंबर को 114 फीसदी के भारी लिस्टिंग गेन के साथ 150 रुपये पर लिस्ट हुआ था। फिर इसमें लगातार दो दिन 10 फीसदी का अपर सर्किट भी लगा। हालांकि, अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के निवेशक जमकर मुनाफावसूली कर रहे हैं। बजाज हाउसिंग के शेयरों में गुरुवार को 10 फीसदी तक गिरावट देखने को मिली। इससे पहले बुधवार को भी बजाज हाउसिंग के शेयरों में गिरावट आई थी। दोपहर 12.45 तक बजाज हाउसिंग के शेयर 7.68 फीसदी की गिरावट के साथ 160.32 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

Bajaj Housing Finance के शेयरों में गिरावट क्यों?

बजाज हाउसिंग का शेयर 188.50 रुपये का हाई बनाने के बाद अब 156.29 रुपये के स्तर पर आ गया है। इसकी बड़ी वजह है कि मार्केट एनालिस्ट की बजाज हाउसिंग को लेकर राय। उनका मानना है कि बजाज हाउसिंग के स्टॉक का वैल्यूएशन काफी अधिक है। कई दूसरे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक काफी सस्ते में मौजूद हैं।

अब लिस्टिंग के बाद निवेशकों का मुनाफा सिर्फ 4.16 फीसदी रह गया है। हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए काफी अच्छा है और आरबीआई निवेशकों को कुछ मुनाफावसूली करके शेयर को होल्ड करना चाहिए।

बजाज हाउसिंग पर क्या है ब्रोकरेज हाउस की राय?

घरेलू ब्रोकरेज फर्म फिलिपकैपिटल ने 210 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कवरेज शुरू की है। उसका कहना है कि बहुत से लोग होम लोन लेने के लिए नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को काफी पसंद करते हैं। खासकर 50 लाख रुपये के लोन टिकट साइज के लिए। इसका बजाज हाउसिंग को फायदा मिल सकता है, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित एनबीएफसी में से एक है।

रेट कट से झूमा अमेरिकी शेयर बाजार, क्या भारतीय स्टॉक मार्केट भी होगा गुलजार?

परिवहन विशेष न्यूज

रेट कट के फैसले पर अमेरिकी शेयर मार्केट ने गुरुवार को जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के तीनों प्रमुख सूचकांकों शुरुआती कारोबार के दौरान तेज उछाल दिखा। इससे उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भी जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार शुरुआती तेजी को बरकरार नहीं रख सके।

नई दिल्ली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार देर रात नीतिगत ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट यानी आधा फीसदी की कटौती की। आर्थिक जानकारों को 25 बेसिस प्वाइंट कटौती की उम्मीद थी। हालांकि, इस पर बुधवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। रेट कट का फैसला आने के बाद अमेरिका के तीनों प्रमुख सूचकांक- Dow Jones, Nasdaq Composite और S&P 500 में रेट कट के बाद थोड़ी तेजी दिखा। लेकिन, आखिर में तीनों गिरावट के साथ बंद हुए।

हालांकि, अमेरिकी शेयर मार्केट ने रेट कट के फैसले पर असली प्रतिक्रिया आज यानी गुरुवार को दी है। शुरुआती कारोबार में तीनों प्रमुख सूचकांकों में एक से लेकर करीब 3 फीसदी तक का उछाल देख गया। गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे) तक Nasdaq Composite 2.79 फीसदी, S&P 500 में 1.85 फीसदी और Dow Jones Industrial Average 1.30 फीसदी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे पता चलता है कि निवेशकों ने रेट का जोरदार इस्तकबाल किया है।

क्या भारतीय शेयर बाजार में भी दिखेगी?

भारतीय बाजार और निवेशक अमूमन अमेरिकी शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार को तेजी देखने को मिल सकती है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार शुरुआती तेजी को बरकरार नहीं रख सके। हालांकि, अंत में यह नए रिकार्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे।

बीएसई का मानक सूचकांक संसेक्स



236.57 अंक की तेजी के साथ 83,184 के नए शिखर पर जाकर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 825.28 अंक बढ़कर

83,773.61 के उच्च स्तर तक पहुंचा था। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 38.25 अंक बढ़कर 25,415.80 के सर्वकालिक उच्च

स्तर पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान यह 25,611.95 के उच्च स्तर तक पहुंचा था।

लगातार चार दिन बंद रहेंगे बैंक, RBI ने पहले ही कर दी छुट्टी की घोषणा



Bank Holiday List भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट के हिसाब से 20 सितंबर से लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी अलग-अलग शहर में रहेगी। ऐसे में कस्टमर को बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक करने के बाद ही बैंक जाना चाहिए। इस आर्टिकल में जानते हैं कि अगले चार दिन तक किस शहर के बैंक में छुट्टी रहेगी।

नई दिल्ली। देश के सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंक के लिए हॉलिडे लिस्ट तैयार करता है। यह लिस्ट साप्ताहिक अवकाश, क्षेत्रीय त्योहार, सैनल हॉलिडे को ध्यान में

रखकर तैयार किया जाता है। सभी राज्यों में बैंक हॉलिडे अलग-अलग दिन होता है। ऐसे में कस्टमर को सलाह दी जाती है कि वह बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List) को चेक करने के बाद ही बैंक जाएं। वैसे तो सितंबर का महीना खत्म होने में 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में अगर आप भी इस महीने बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि कल यानी 20 सितंबर से लगातार 4 दिन तक बैंक में छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी हर शहर में अलग-अलग होगी। इन छुट्टी में बैंक के साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं।

बैंक का साप्ताहिक अवकाश आरबीआई के अनुसार देश के सभी बैंक रविवार के दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा महीने के दूसरे-चौथे शनिवार को भी बैंक में कोई कामकाज नहीं होगा।

किस शहर के बैंक बंद रहेंगे आरबीआई के बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार-

● 20 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर के

बैंक बंद रहेंगे। इस दिन ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की वजह से बैंक में छुट्टी दी गई है।

- 21 सितंबर को श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के अवसर पर केरल के बैंक में छुट्टी रहेगी।
- 22 सितंबर को रविवार है यानी बैंक का साप्ताहिक अवकाश। इस दिन सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।
- महाराजा हरी सिंह जी का जन्मदिन के अवसर 23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर के बैंक बंद रहेंगे।
- इसके अलावा 28 सितंबर और 29 सितंबर को साप्ताहिक अवकाश की वजह से देश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।
- चालू रहेगी ये सर्विस** बैंक हॉलिडे वाले दिन भी कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) की सुविधा ले सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन बैंकिंग 24*7 के लिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा एटीएम (ATM) सर्विस भी सुचारू रूप से चलती है।

भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, शेयर मार्केट का क्या रहेगा हाल?

एसएंडपी ग्लोबल का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार समुद्र के जरिये होता है ऐसे में बढ़ते निर्यात और थोक वस्तु आयात को प्रबंधित करने के लिए मजबूत बंदरगाह बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में घरेलू ऊर्जा की मांग बढ़ रही है।

मुंबई। एसएंडपी ग्लोबल ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा कि अगर चालू वित्त वर्ष में 6.7 प्रतिशत की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर को आधार मानें तो भारत 2030-31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में 8.2 प्रतिशत की विकास दर के साथ लाजिस्टिक में सुधार, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पूंजी पर निर्भरता कम करने के लिए निरंतर सुधार करने होंगे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मजबूत विकास संभावनाओं और बेहतर विनियमन के कारण इक्विटी बाजारों के गतिशील और प्रतिस्पर्धी बने रहने की उम्मीद है। इतना ही नहीं भारत के प्रमुख उभरते बाजार सूचकांकों में शामिल होने के बाद से भारतीय सरकारी बॉन्ड में विदेशी प्रवाह बढ़ गया है, जिससे भविष्य में और वृद्धि होने की उम्मीद है। 'ईडिया फारवर्ड: इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स' रिपोर्ट के पहले संस्करण में कहा गया है कि भारत का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार समुद्र के जरिये होता है, ऐसे में बढ़ते निर्यात और थोक वस्तु आयात को प्रबंधित करने के लिए मजबूत बंदरगाह बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में घरेलू ऊर्जा की मांग बढ़ रही है और यह अक्षय ऊर्जा और कम उत्सर्जन वाले ईंधन सहित टिकाऊ प्रौद्योगिकियों पर काम कर सकता है।

ऋषभ पंत ने टेकजाँकी में खरीदी 2 फीसदी हिस्सेदारी, जानिए क्या करती है कंपनी?



परिवहन विशेष न्यूज

TechJockey.com की नींव 2017 में जोमैटो के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट आकाश नांगिया ने अपने कॉलेज के दोस्त और पूर्व McKinsey एजीक्यूटिव अर्जुन मित्तल के साथ मिलकर की थी। यह देशभर में छोटे बिजनेस वाले सॉफ्टवेयर वेंडर्स को जोड़ती है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने अपने कामकाज का विस्तार अमेरिकी बाजार में भी किया है। टेकजाँकी ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 125 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया।

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मार्केटप्लेस TechJockey.com में भारी निवेश किया। टेकजाँकी के मुताबिक, पंत ने कंपनी में 2 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। यह साढ़े 7.40 करोड़ रुपये में हुआ।

क्या करती है TechJockey.com TechJockey.com की नींव 2017 में जोमैटो के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट आकाश नांगिया ने अपने कॉलेज के दोस्त और पूर्व McKinsey एजीक्यूटिव अर्जुन मित्तल के साथ मिलकर की थी। यह देशभर में छोटे बिजनेस वाले सॉफ्टवेयर वेंडर्स को जोड़ती है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने अपने कामकाज का विस्तार अमेरिकी बाजार में भी किया है। टेकजाँकी ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 125 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया। उसने मौजूदा वित्त

वर्ष में 170-180 करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।

नांगिया ने एक बयान में कहा कि फ्रेश इक्विटी 370 करोड़ रुपये (लगभग 44.17 मिलियन डॉलर) के वैल्यूएशन पर जुटाई गई। इसमें पंत ने कंपनी में 2 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। उन्होंने कहा, 'ऋषभ पंत का बॉर्ड में शामिल होना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। उनका न सिर्फ बतौर क्रिकेटर कद काफी बड़ा है, बल्कि उनकी कारोबारी समझ भी काफी शानदार है।'

पंत ने टेकजाँकी में निवेश क्यों किया? आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने वाले पंत का कहना है कि अलग-अलग व्यवसायों में निवेश करने के लिए सचेत समझ की जरूरत है। इस मामले में फैसला लेने के लिए वह अपने प्रोफेशनल स्पेर्ट्स करियर के अनुभव का भी इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (SaaS) फर्मों के उभार के बारे में पंत ने कहा, 'मुझे असल में SaaS कंपनियों के संचालन का तरीका पसंद है। मुझे उस कॉन्सेप्ट में काफी संभावनाएं नजर आती हैं।' पंत ने कहा, 'क्रिकेट में लाइव स्ट्रीमिंग, कमेंट्री और DRS के लिए सही तकनीक का होना महत्वपूर्ण है। सही तकनीक से आपका फौरन स्टाट डिस्टीनक्शन लेने में मदद मिलती है। मैंने देखा है कि सही सॉफ्टवेयर किसी व्यवसाय को कुशलतापूर्वक विकसित करने में कितनी मदद कर सकता है। इसलिए मैंने TechJockey.com में अपने निवेशक को सही समझता हूँ।'

हे भगवान! अब हरे-भरे इलाकों में भी बढ़ रहा ओजोन प्रदूषण, दिल्ली की 10 जगहों पर ज्यादा दिन रही मौजूदगी

परिवहन विशेष न्यूज़

राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में रह रहे लोगों की चिंता एक खबर बढ़ा सकती है। वह है ओजोन प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। हालांकि राहत की बात ये है कि दिल्ली-एनसीआर के उन इलाकों की पहचान कर ली गई है। जहां पर इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। इस खबर के माध्यम से पहिए राजधानी के वो 10 प्रभावित क्षेत्र।

नई दिल्ली। ओजोन प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम महानगरों में रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, थोड़ी राहत की बात यह कही जा सकती है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ओजोन प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। इससे इन क्षेत्रों में ओजोन प्रदूषण की रोकथाम में आसानी होगी।

हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर की माप के लिए आमतौर पर पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषक कणों की मौजूदगी को ही

मुख्य आधार बनाया जाता है। लेकिन, हाल के कुछ सालों में दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर बड़े शहरों में ओजोन प्रदूषण कणों का स्तर बढ़ा है। सतह पर मौजूद ओजोन के कणों को सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।

इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए भी विशेष प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया जाता है। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों के ऐसे निगरानी केन्द्रों की पहचान की है जहां पर ओजोन प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है।

जबकि, ऐसे आठ स्टेशनों की पहचान भी की गई है जहां पर एक दिन भी ओजोन प्रदूषण का स्तर मानकों से ज्यादा नहीं रहा है। ओजोन प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए एक अप्रैल 2024 से 18 जुलाई 2024 तक के डाटा का विश्लेषण किया गया है।

हरे-भरे इलाके प्रभावित, सघन क्षेत्रों में राहत
ओजोन प्रदूषण की एक और खास बात देखने को मिली है। दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज और नरेला जैसे क्षेत्र अपेक्षाकृत कम बसावट वाले और हरे-भरे हैं। लेकिन, यहां को हवा में 78

दिन ओजोन प्रदूषण की मौजूदगी रही है।

दूसरी ओर, आयातगर, चांदनी चौक, पूसा और इहबास जैसे घनी बसावट वाले इलाकों में स्थित निगरानी केन्द्रों में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब ओजोन प्रदूषण का स्तर मानकों से ज्यादा हो।

क्या है ओजोन प्रदूषण के मानक
सतह पर मौजूद ओजोन प्रदूषण को मापने के लिए आठ घंटे के औसत को आधार बनाया जाता है। मानकों के मुताबिक किसी भी निगरानी केन्द्र में आठ घंटे के औसत में ओजोन प्रदूषण का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा होने पर उसे ओजोन प्रदूषण वाला दिन माना जाता है।

कैसे बनता है ओजोन प्रदूषण
सतह पर मौजूद ओजोन प्रदूषण कणों का कोई सीधा स्रोत नहीं होता। बल्कि, ये प्रदूषक कण नाइट्रोजन आक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (वीओसी) के बीच तेज धूप के दौरान होने वाली रासायनिक क्रिया के दौरान पैदा होते हैं। नाइट्रोजन आक्साइड और वीओसी के स्रोत मुख्यतौर पर वाहनों

और फैक्टरियों और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाला धुआं है।

इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक

विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र की कार्यकारी निदेशक (शोध एवं परामर्श) अनुमिता रायचौधुरी बताती हैं कि जमीन की सतह पर मौजूद ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस होती है। सेहत पर जिसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं।

श्वंस संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोग, आस्थमा और क्रानिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डीजीजे से पीड़ित लोग, बच्चों और बुजुर्गों को इससे ज्यादा परेशानी होती है।

ऐसी हवा में सांस लेने से श्वसनली में सूजन और क्षति हो सकती है। फेफड़े संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं और क्रानिक ब्रोकाइटिस बढ़ सकता व अस्थमा के दौरे की आवृत्ति भी बढ़ सकती है।

गैसीय प्रदूषण की रोकथाम पर हो जोर

विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र के मुताबिक धूलकणों की ज्यादा मात्रा वाले प्रदूषक कण पीएम 10 की रोकथाम पर आमतौर पर

ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन, गैसीय प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विस्तृत कार्ययोजना की जरूरत है।

खासतौर पर वाहन, उद्योग, कुकिंग और टोस ईंधन, खुले में कचरा जलाने और रासायनिक क्रिया के जरिए होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए टोस उपाय किए जाने की जरूरत है।

दस जगहों पर सबसे ज्यादा दिन रहा ओजोन प्रदूषण जगह

जगह	दिन
कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	78 दिन
नरेला	78 दिन
नांजल पार्क	75 दिन
जेएनएन स्टेडियम	71 दिन
अलीपुर	69 दिन
आरके पुरम	69 दिन
नेशनल स्टेडियम	68 दिन
नेहरू नगर	67 दिन
सेक्टर-1 नोएडा	66 दिन
बवाना	63 दिन

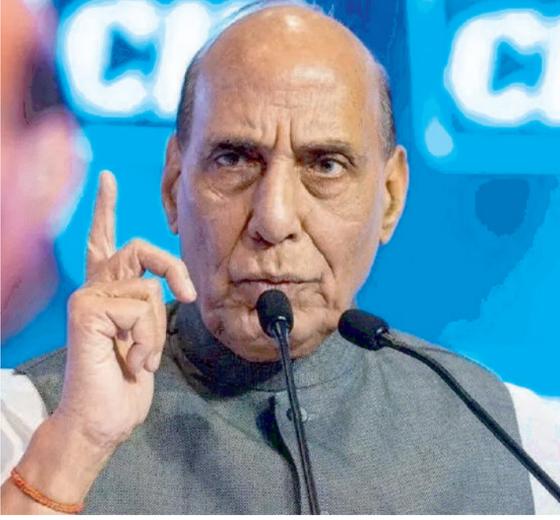
हिंद महासागर में भारत पसंदीदा सुरक्षा साझेदार', राजनाथ सिंह बोले- 2047 तक नौसेना को बनाएंगे पूर्ण आत्मनिर्भर

परिवहन विशेष न्यूज़

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नौसेना के कमांडरों की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में देखा जाता है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि अब नौसेना को एक खरीददार से वर्ष 2047 तक पूर्णतया आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अब हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में शांति और समृद्धि बढ़ाने में महती भूमिका निभाने के लिए सराहने करते हुए कहा कि यह क्षेत्र आर्थिक, जियोपॉलिटिकल, व्यापारिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद मूल्यवान और संवेदनशील है।

रक्षा मंत्री ने गुरुवार को यहां नौसेना के कमांडरों की दूसरी बैठक में जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों आदि से लैस करके उसकी क्षमताओं को बढ़ाकर उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है। अब नौसेना को एक खरीददार से वर्ष 2047 तक पूर्णतया



आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा।

64 जहाज और पनडुब्बियां निर्माणाधीन: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय शिपयार्डों में मौजूदा समय में 64 जहाजों और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं। 24 अतिरिक्त प्लेटफार्मों पर भी निर्माण के आदेश दिए गए हैं। पिछले पांच सालों में नौसेना के आधुनिकीकरण बजट के दो-तिहाई हिस्से को स्वदेशी अधिग्रहण में खर्च किया गया है। इससे घरेलू डिफेंस इकोसिस्टम में बढ़-चढ़कर विकास हुआ है। उन्होंने सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण को

स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले भारत को समुद्री तटों वाले और जमीन से घिरे देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे द्वीप देश के रूप में देखा जाता है, जिसकी जमीन पर भी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इससे ही यह महासागरीय क्षेत्र बहुमूल्य बनता है, लेकिन इसी क्षेत्र में समुद्री लुटेरों, जहाजों के अपहरण, ड्रोन हमले, मिसाइलों के हमले और समुद्री केबिल कनेक्शन में बाधा आना भी इसे अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।

पितरों को दें जलांजलि

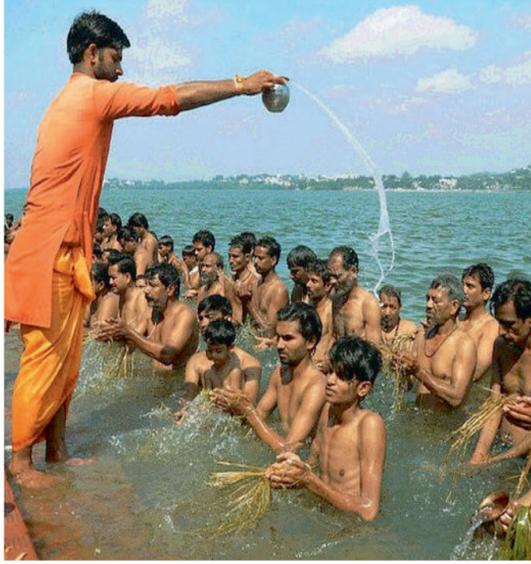
श्राद्ध पक्ष में और प्रत्येक अमावस्या व संक्रांति के दिन पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है।

पितरों को जल अर्पित करने की विधि इस प्रकार है:-

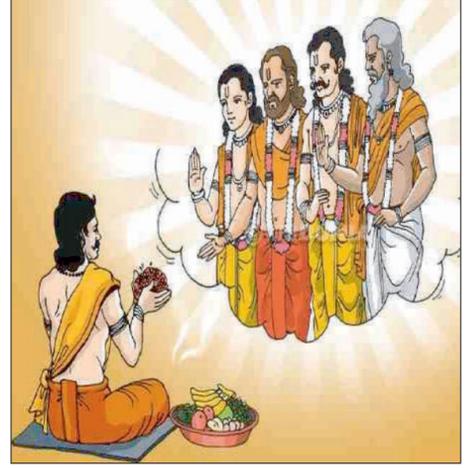
- * श्राद्ध के दौरान, अंगूठे से पितरों को जल अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंगूठे से जल देने से उनको आत्मा को शांति मिलती है।
- * पितरों को जल अर्पित करने के लिए, सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें।
- * हाथों में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प, और काले तिल लें।
- * दोनों हाथ जोड़कर पितरों का स्मरण करें।
- * पितरों को आमंत्रित करें और जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें।
- * इसके बाद, 5-7 या 11 बार अंजलि से जल धरती पर गिराएं।
- * पितरों को जल देते समय 'ॐ पितृ देवतायै नमः' मंत्र का जाप करने से भी पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।

* आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं:- (रं अंगच्छन्तु नमः पितरं एवं ग्रहन्तु जलान्जलिम् ॥ (सबसे पहले आप शांति से व अपने पितरों के प्रति श्राद्ध भाव करके बैठें। फिर आप दाहिनी हथेली की अंजलि में जल लें, अब कुछ दाने काले तिल के लीजिए, पुष्प, अक्षत इत्यादि भी ले सकते हैं। फिर अपने पितरों को याद करते हुए जल को अंगूठे की तरफ से धीरे-धीरे धरती पर छोड़िए। उसके उपरांत पितरों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें।)

॥ ॐ पितृ देवतायै नमः ॥



(पितृ-दोष)



कैसे बनता है पितृ दोष:-

- * ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब व्यक्ति की कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और दसवें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति हो जाती है, या फिर सूर्य पर शनि/ राहु का प्रभाव हो तो पितृ दोष बनता है।
- * लग्नेश यदि छठे आठवें बारहवें भाव में हो व लगन में राहु हो तो और सूर्य भी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हो तो भी पितृदोष बनता है।
- * यह एक ऐसा दोष होता है जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि पितृ दोष की वजह से हमारे पितर (पूर्वज) हमारा किसी रूप से सहयोग नहीं कर पाते/और बिना पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुखों का अभाव बना रहता है। पितृ दोष की वजह से आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, विवाह में बाधा, संतान बाधा आदि सभी तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं।

पितृ दोष के उपाय:-

- * श्राद्ध पक्ष में पितरों का विधिवत तर्पण करें और श्राद्ध पूरी श्रद्धा से निकालें।
- * संध्य के समय एक दीपक पितरों के नाम का परिंडे में या तुलसी वृक्ष के पास जलाएं।
- * श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को ध्यान करके गायों की सेवा करें उन्हें गुड़, दाना, चारा इत्यादि खिलाएं।
- * पितृ दोष से निजात पाने के लिए किसी पवित्र नदी में काले तिल डालकर तर्पण करें। ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं।
- * अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करके किसी सुपात्र ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न, फल और दक्षिणा देकर उससे आशीर्वाद लें।
- * श्राद्ध पक्ष में व अमावस्या के दिन गीता के पाठ करें, गीता का सातवां अध्याय जरूर पढ़ें और भगवान से पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें।

'गोवा में पर्यटकों को परेशान किया जा रहा', बीजेपी विधायकों का ट्रैफिक पुलिस पर आरोपी; डीजीपी से की मुलाकात

परिवहन विशेष न्यूज़



गोवा में बीजेपी विधायकों ने राज्य की ट्रैफिक पुलिस पर पर्यटकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायकों ने डीजीपी आलोक कुमार से ट्रैफिक पुलिस की शिकायत की है। विधायकों का कहना है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को यातायात पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। दस्तावेजों की जांच के बहाने यातायात पुलिस अक्सर परेशान करती है।

गोवा के भाजपा विधायकों के एक समूह ने गुरुवार को डीजीपी आलोक कुमार से मुलाकात की। उन्होंने डीजीपी से शिकायत कर आरोप

लगाया कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को यातायात पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है।

पुलिस पर पर्यटकों को परेशान करने का आरोप

विधायकों ने कहा कि पर्यटक अक्सर किराए पर वाहन लेते हैं, उन्हीं के दस्तावेजों की जांच के बहाने यातायात पुलिस अक्सर परेशान करती है। विधायकों ने यह भी दावा किया कि इन्हीं सब वजहों से राज्य में लगातार पर्यटकों की संख्या में कमी आती जा रही है।

डीजीपी से की शिकायत
भाजपा विधायक माइकल लोबो (कलंगुटे), केदार नाइक (सालीगाओ) और डेलिलाह लोबो

(सिओलिम) ने डीजीपी से मुलाकात की। इन लोगों ने पर्यटकों को हो रही परेशानी को रोकने के लिए यातायात पुलिस को निर्देश जारी करने की मांग की।

क्यूआर कोड आधारित प्रणाली होगी शुरू
भाजपा विधायक के अनुसार, डीजीपी यातायात पुलिस विभाग को पर्यटकों को परेशान नहीं करने का निर्देश देने के लिए सहमत है। विधायक नाइक ने बताया कि डीजीपी का कहना है कि एक क्यूआर कोड आधारित प्रणाली शुरू की जाएगी कि एक बार किसी विशेष पर्यटक के वाहन से संबंधित दस्तावेजों की जांच हो जाने के बाद उसी व्यक्ति को फिर से उसी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े।

ओड़िशा प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं खिलाफ मामला दर्ज किए

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भारत जैसे सभ्य समाज और शांति, मित्रता और भाईचारे वाले देश में कोई भी मोदी सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राहुल गांधी के प्रति दिए गए अशुभ बयान को स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके सहयोगी दलों के विधायकों द्वारा इस तरह से कई आपत्तिजनक टिप्पणियां किये जाने की आशंका है। उनके खिलाफ टोस कार्रवाई की मांग को लेकर ओड़िशा प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा कल भुवनेश्वर के खारवेल नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सभी नेता शामिल हुए। इसी पदार्थन में बरिष्ठ नेता प्रसाद हरिचंदन, श्रीकांत जेना, जायदेव जेना, निरंजन पटनायक और महम्मद मोकिम शामिल हुए थे।



कविता : कांग्रेस : ये न हो स्टंट

कांग्रेस में चेहरे हैं तीन और पद है एक। खड़े भी देने लगे सलाह इरादे है नेक। तय होगा विधायक दल की मीटिंग में, आलाकमान का यहाँ बोलेंगा विवेक। आया राम गया राम की इस धरती पर, बागी विधायक जम के लगाएंगे जैक। क्या वोटों के काम आएंगे सात वादे? ये आने वाली सरकार के हैं नेक इरादे। अब महिलाओं को देंगे दो हजार महीना, विपक्षियों को लगता है ये कदम सही ना। पाँच सौ के सिलेंडर से कोई कसर रही ना, बुद्धापे,दिव्यांग,विधवा पेंशन गुजरें महीना। इससे विरोधी पार्टी को लगा बिजली करंट, अरे कांग्रेस ने तो पा लिया जबरदस्त फ्रंट। अब मांग रही है जनता दुआ ये न हो स्टंट।

संजय एम . तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986



कविता : शैलजा है नाराज ?

सिरसा की बेटे शैलजा हो गई है नाराज, किसकी जीत पर लगे ब्रेक होगा परवाज। ये जातिगत टिप्पणी किसको पड़ेगी भारी, लगता है जीती सीट भी जाए न कोई हारी। इक्कीस सीट पर इस बेटे का बड़ा प्रभाव, ये कैसी विडंबना कोई भी दे नहीं रहा भाव। ना जाणु टिकट वितरण क्यों करी अनदेखी? भारी न पड़ जाए भैया किसी की भी शेखी। शैलजा अभी-भी चुप है प्रचार से विमुख है, हड़ड़ा जी को भी डुख है, सता तो प्रमुख है।

पोस्टर व बयानबाजी से सब में है तनातनी। क्या? संदेश यात्रा और कौनसा मांगे हिसाब? ये हरियाणा की जनता अब मांग रही जवाब। ये सिरसा की बेटे शैलजा हो गई है नाराज, किसकी जीत पर लगेगा ब्रेक होगा परवाज।

संजय एम . तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986